चीनी मिलों के लिए फीका रहेगा फेस्टिव सीजन!

शुगर मिलों को कर्ज देने से कतरा रहे हैं बैंक, शुगर स्टॉक में 20 लाख टन की हो सकती है कमी

[अनिंद्य उपाध्याय | नई दिल्ली]

चीनी के सरप्लस स्टॉक के कारण त्योहारी सीजन में इसके दाम नहीं बढ़े हैं। हालांकि, आने वाले महीनों में स्टॉक में 20 लाख टन का डेफिसिट देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बैंक चीनी मिलों को वर्किंग कैपिटल (कामकाजी पूंजी) देने से मना कर रहे हैं।

बैंकर्स और शुगर इंडस्ट्री एग्जिक्यूटिव्स का कहना है कि राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत चीनी के दाम कम होने के समय भी गन्ने की कीमतें ऊंची रखी जा रही हैं, जिसके कारण मिलों के लिए कामकाज व्यावहारिक नहीं रह गया है। राज्य में 95 चीनी मिलों में से करीब 70 मिलों को सस्पेंशन नोटिस दिया गया है और वे अगले महीने कामकाज शुरू नहीं कर पाएंगी।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के मुताबिक, इन मिलों ने 2013-14 में 47 लाख टन चीनी का प्रॉडक्शन किया था। शुगर इंडस्ट्री एसोसिएशन के सूत्रों ने इकनॉमिक टाइम्स को बताया, 'दिसंबर के बाद कामकाज स्थगित रहने से न केवल सरप्लस शुगर स्टॉक का 20 लाख टन हिस्सा खत्म होगा, बल्कि अगले सीजन में ओवरऑल प्रॉडक्शन में 20 लाख टन से ज्यादा की कमी भी देखने को मिलेगी।' एसबीआई ने पिछले महीने यूपी सरकार को लिखा था कि वह राज्य में चीनी मिलों को कर्ज देकर जोखिम नहीं उठा सकती है। दूसरे सरकारी बैंकों ने भी कुछ इसी तरह की चिंताएं जाहिर की हैं।

चीनी के दाम कम होने के समय भी गन्ने की कीमतें ऊंची रखी जा रही हैं, जिसके कारण मिलों के लिए कामकाज व्यावहारिक नहीं रह गया है

एक बड़े सरकारी बैंक के मुताबिक, शुगर इंडस्ट्री को आंतरिक स्तर पर 'प्रतिकूल' क्रेडिट रेटिंग दी गई है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें उनकी नेगेटिव लिस्ट में हैं। इसका मतलब है कि अगले महीने से शुरू होने वाले नए शुगर सीजन में बैंक चीनी मिलों को उधारी देने से दूरी बना सकते हैं। एक बड़े सरकारी बैंक के सीनियर ऑफिसर ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर इकनॉमिक टाइम्स को बताया, 'एक बड़ी चीनी कंपनी का एकाउंट नॉन-परफर्मिंग एसेट (एनपीए) में तब्दील हो गया है। यूपी की शुगर मिलों में एक्सपोजर रखने वाले सभी सरकारी बैंकों ने इन कंपनियों को नेगेटिव लिस्ट में डाल रखा है। इसका मतलब है कि बैंक इन कंपनियों को आगे कर्ज देने से बचेंगे।'

चीनी मिलों का नुकसान लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले चार वर्षों में प्रॉडक्शन कॉस्ट 70 फीसदी तक बढ़ गई है, जबकि चीनी की कीमतों में केवल 8 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। यूपी में चीनी मिलों की प्रति किलो प्रॉडक्शन कॉस्ट 36-37 रुपये है, जबकि इसका रेट 28.5-29 रुपये प्रति किलो है। एक प्रमुख शुगर कंपनी के सीईओ ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया, 'अगर हम 1 दिसंबर तक ऑपरेशंस शुरू नहीं करते हैं तो किसान परेशान हो जाएंगे...1 दिसंबर के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। बड़ी संख्या में किसान आधे दाम पर गुड़ मैन्युफैक्चरर्स को गन्ना बेचने के लिए मजबूर होंगे।'

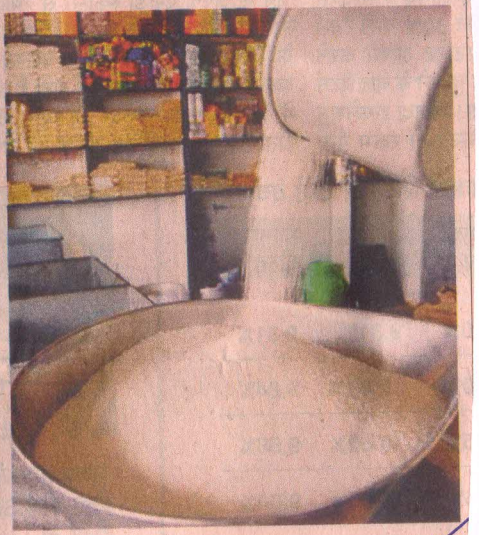

इकनॉमिक टाइम्स
8/10/14